but this year there will be no crop of cotton. As there was shortage of cotton in the country, it was decided that 14 lakh bales of cotton will be imported, but now there will be more shortage.

The farmers who produce cotton seeds are not responsible for this but it is some individual merchants who distribute the seeds who are responsible.**

14 hrs.

MR. DEPUTY-SPEAKER : It will not go on record. I am very sorry; if you make individual attacks on anybody, who is not a Member of this House, it will not go on record.

SHRI ANANT DAVE :**

MR. DEPUTY-SPEAKER : You cannot misuse the permission given under Rule 377 and attack some individual who happens to be somewhere else.

SHRI ANANT DAVE : Our handloom trade will not get sufficient cotton this year and this is a national loss also. I would like to know whether the Minister of Civil Supplies would assure the poor farmers of Gujarat and other people that proper investigations would be made and persons who have committed such scandals would be punished.

(ix) ATTEMPTS OF MONOPOLY HOUSES TO SCUTTLE RS. 100 CRORE GOVERNMENT SUPPORTED NEWSPRINT PROJECT OF MYSORE PAPER MILLS

श्रीमती मृणाल गोरे (बम्बई उत्तर) : मैसूर पेपर मिल के कारोबार के बारे में मैं कुछ तथ्य उद्योग मंत्री के ध्यान में लाना चाहती हूं। सभी जानते हैं कि न्यूजप्रिंट आयात करने में काफी फारेन एक्सचेंज हमको खर्च करनी पड़ रही है। इसको देखते हुए 1975 में 75000 टन न्यूजप्रिंट इम्पोर्ट करने के लाइसेंस दिए गए थे। मैसूर पेपर मिल की सौ करोड़ की एक पांच साला प्रोजेक्ट है। अगर यह प्रोजेक्ट सफल हो जाये और पूरी हो जाए तो विदेशी मुद्रा की काफी बचत हो सकती है। लेकिन हो यह रहा है कि तीन जो बड़े बिजनेस हाउसिस हैं, जालोन, हरिहर फोलीफाइबर जो बिड़लाज की कम्पनी हैं और वैस्ट कोट पेपर मिल जो बांगुर और सोमानी की है ये तीनों मिलकर मैसूर पेपर मिल पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैसूर पेपर मिल में काफी हद तक कर्नाटक सरकार के शेयर हैं। गवर्नमेंट आफ इंडिया चाहती है कि उसका एक्सपेंशन हो जाये और वहां पर जल्दी प्रोडक्शन शुरू हो जाये। लेकिन हम देख रहे हैं कि 32 करोड़ का उनको जो लोन वगैरह चाहिये वह कहीं उसको न मिल जाये इस वास्ते ये तीन बड़े बिजनेस हाउसिस बहुत कोशिश कर रहे हैं। साथ ही उसको रॉ मैटीरियल न मिले इसकी भी काफी कोशिशें इन लोगों की तरफ से हो रही हैं। हरिहर पोलीफाइबर्ज को उसकी जरूरत से ज्यादा युकलिपटस वुड दिया गया है, उसको जरूरत पचास हजार टन की है जब कि उसको 75 हजार टन दिया गया है। इस प्रकार से रा मैटीरियल को कार्नर करने का काम भी चल रहा है। इस कम्पनी में काफी शेयर छोट शयरहोल्डर्स के हैं। आई०डी०बी०आई० से जो लोन वगैरह उसको दिया जाना हैं वह भी इसको नहीं मिल रहा है। ऐसी परिस्थितियां बिड़ला के हाउसिस, वैस्ट कोस्ट पेपर्स मिल्ज या बांगुर हाउसिस, जालोन हाउस की तरफ से मिल कर पैदा करने की कोशिश की जा रही है, ताकि यह योजना आगे न बढ़ सके। उद्योग मंत्री से मैं अर्ज करूंगी कि जब आपने एलान कर दिया है कि बड़े इंडस्ट्रियल हाउसिस को आगे बिकास करने का आप मौका नहीं देंगे तब असल में जो यहां स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है उसको आप नजर में रखें और देखें कि इनकी ये कोशिशें सफल न हों।

**Not recorded.